

संपादकीय

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। -रोबिन शर्मा

विश्व बैंक ने लगाई मुहर :
मोदी ने भेदा गरीबी के
चक्रव्यूह का मायाजाल

मार्वर्ती क्षेत्रों में भारी तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बालद मंडराने के मध्य भारत में गरीबी के मोर्चे पर वर्ल्ड बैंक से एक अच्छी खबर आई है। देश में गरीबी तेजी से घट रही है और इससे आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। वर्ल्ड बैंक की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले दस साल में गरीबी को कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह भी कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस सालाना मेहनत आखिर रंग लाई, जब विश्व बैंक ने भारत में गरीबी के मायाजाल के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफलता हासिल करने पर अपनी मुहर लगा दी। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट मोदी के गरीबी कम करने के दावों की पुष्टि करता है। अस्सी करोड़ गरीबों को खाद्य सहायता प्रदान करने वाले भारत की गरीबी पर लगातार हो रहे सर्वे और अध्ययन रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन और विश्लेषण करें तो पायेंगे, अब तक देश गरीबी से मुक्त हो गया होगा। जब भी गरीबी से मुक्ति की कोई रिपोर्ट आती है तो हमारी खुशी का टिकाना नहीं रहता की हम गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो रहे हैं। लगता है हमारे देश की गरीबी किसी मायाजाल से कम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश में अत्यधिक गरीबी 16.2 प्रतिशत थी जो 2022-23 में घटकर 2.3 प्रतिशत पर आ गई है। अत्यधिक गरीब का मतलब ऐसे लोगों से है जिनका रोजाना खर्च 2.15 डॉलर (करीब 180 रुपये) से भी कम है। यह खबर हमारे लिए सुकूनदायी कही जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। गाँवों में अत्यधिक गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह शहरों में यह आंकड़ा 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत रह गया है। पाँच सबसे अधिक आवादी वाले राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश—में 2011-12 में देश के 65 प्रतिशत अति गरीब रहते थे और 2022-23 तक अत्यधिक गरीबी में कुल गिरावट में दो-तिहाई का योगदान दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब निम्न-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। स्वतंत्र विश्लेषक इसे किसी चमत्कार से कम नहीं

दुनिया भर में गरीबी की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक है। हमारे देश की बात

करें तो आजादी के 78 सालों के बाद भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासा हो रहा है। पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन के प्रयास जरूर सिरे चढ़े हैं। भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। रिपोर्ट में पिछले नौ वर्षों में भारत में करीब 25 करोड़ लोगों के गरीबी के अधिकांशप्रति से मुक्त होने का दावा किया गया था वहीं भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में पहली बार ऐतिहासिक रूप से गांवों में गरीबी में तेजी से कमी आई है और एक साल के भीतर यह 5 फीसदी से नीचे आ गई है। यह मुख्य रूप से सरकारी सहायता कार्यक्रमों के प्रभावों के कारण संभव हुआ है। यह भी कहा गया कि मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर खास ध्यान दिया है। इसका असर जमीन पर दिख

रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की बात करे तो भारत का स्थान 127 देशों में 105वां है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में वर्ष 2024 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में भारत कुल 125 देशों में से 111वें स्थान पर था। हालांकि, सरकार ने त्रिपुर्यो कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए इस सूचकांक में भारत के प्रदर्शन का विरोध किया था।

एसबीआई रिसर्च के पेपर में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी 2023-24 में घटकर 4.86 फीसदी हो जाएगी, जो पिछले साल 7.2 फीसदी थी। 2011-12 में यह 25.7 फीसदी थी। इस बीच शहरी क्षेत्रों में 2024 में साल-दर-साल गिरावट धीमी रही। एसबीआई रिसर्च ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में यह 4.09 फीसदी थी, जबकि पिछले साल यह 4.60 फीसदी थी। रिपोर्ट में ग्रामीण गरीबी में तेज कमी का श्रेय निम्न आय वर्ग के बीच खपत वृद्धि को दिया गया है, जिसे मजबूत सरकारी समर्थन से बल मिला है। शहरी गरीबी में भी तेजी से कमी आई है, जो अब 4.09 फीसदी होने का अनुमान है, जो 2011-12 में 13.7 फीसदी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी अनुपात में तेज गिरावट महत्वपूर्ण सरकारी सहायता के साथ कंजम्पशन ठोथ का नतीजा है।

दूनिया भर में गरीबी की स्थिति आज भी बेहत चिंताजनक है। हमारे देश की बात करें तो आजादी

दुनिया भर म गरीबों का स्थिति आज भा बहद चिंताजनक हो। हमारा दरशा का बात कर तो आजादी के 78 सालों के बाद भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासा हो रहा है। पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन के प्रयास जरूर सिरे चढ़े हैं। भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना, सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मात्र स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के इंधन वितरण, सौभाग्य के माध्यम से विजली कवरेज में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने साधूहिक रूप से लोगों की रहने की स्थिति और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली मूलभूत समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत 2047 बनने की ओर अग्रसर हो सके। सरकारी स्तर पर यदि ईमानदारी से प्रयास किये जाये और जनधन का दुरुपयोग नहीं हो तो भारत शीघ्र गरीबी के अभिशाप से मुक्त हो सकता है।

-आताथ सम्पादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

क्या 'ई-लाइब्रेरी' रीडर्स को राहत प्रदान कर पाएगी...



आवनाश जाशा

है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या खोतों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से कई प्रकार कि सूचनाएं तथा विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना ई-लाइब्रेरी का भाग है। ई-लाइब्रेरी में सभी स्तर के अनुसार अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसमें आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहती है। ई-लाइब्रेरी अनुसंधान कार्य को अत्यंत सरल बना देती है क्योंकि इसके द्वारा समस्त प्रकार की अधिगम और अनुसंधान संवर्धित सूचनाएं तथा लिखा हुआ लेख अधिगमकर्ताओं तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। ई-लाइब्रेरी द्वारा अधिगम या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बहु माध्यम नेटवर्किंग आदि। इन सभी की सहायता से ई-लाइब्रेरी बहुत ही सरल और आसान बन गई है। ई-लाइब्रेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी का ही एक पारूप है। यह उन लोगों के लिए अत्यंत निःसंदेह एक क्रांतिकारी पहल है जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए समाज को ज्ञान से जोड़ने का कार्य करती है। इससे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDLI), eGranthalaya, Bharatavani जैसी पहले यू ही लाखों डिजिटल संसाधन मुफ्त में उपलब्ध करा रही हैं। भविष्य में इन ई-लाइब्रेरी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का प्रयोग करा पाठकों को उनके रुचि और जरूरत के अनुसार पुस्तकें सुझाई जा सकेंगी। इसके अलावा, स्थानीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ावा देकर यह पहल देश की भाषाई विविधता को भी सम्मान देगी।

भारत में ई-लाइब्रेरी सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि यह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है, जो आने वाले समय में शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक जागरूकता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

मोबाइल ऐप की मदद से भी ई-लाइब्रेरी को और अधिक सलभ और

प्रारूप हा यह उन लागा के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनके पास समय की कमी है। इन लोगों के पास यह सुविधा होती है कि वे ऑनलाइन किताबें पढ़ सकें। इसमें उड़ें पत्रे पलटने की भी जरूरत नहीं होती। सरकारों को ई-लाइब्रेरी की सुविधा विकसित करने के लिए काम करना चाहिए और फॅंडिंग के लिए आगे आना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए यह वरदान हो। ई-लाइब्रेरी से आपको बाजार में आई नई किताबों के बारे में जानकारी मिल जाती है। आपके मनपसंद लेखक की कौन सी नई किताब आई, इसके बारे में आपको पता लग जाता है।

हादि ई-पुस्तकों का यह पहल भाषाई समानता और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे हिंदी भाषी समुदाय के पाठकों को डिजिटल सुग्र में सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। भारत में डिजिटल ईंडिया, नई शिक्षा नीति (NEP 2020), और ग्रामीण डिजिटलीकरण जैसे अभियानों के साथ ई-लाइब्रेरी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल प्रतीत होता है। जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुँच गाँवों तक विस्तारित हो रही है और स्मार्टफोन उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे डिजिटल पुस्तकालयों की उपयोगिता और माझ भी तेज़ी से बढ़ेगी। इस मुहिम लाइब्रेरी का आर आधिक सुलभ और प्रभाशाली बनाया जा सकता है। आज के समय में स्मार्टफोन हर हाथ में है, और इसी तकनीक का लाभ उठाते हुए ई-लाइब्रेरी सेवाएँ अब मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पाठक कहीं भी और कभी भी किताबें पढ़ सकते हैं-चाहे वे घर पर हों, यात्रा में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में। इन मोबाइल ऐप्स में सरल यूजर इंटरफ़ेस, ऑफलाइन पढ़ने की सुविधा, बुकमार्किंग, नोट्स जोड़ने और भाषा चयन जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं, जो पाठकों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए भी सेमटा दखाइ दिता है जब भा किस नगर का निर्माण किया जाता है तो स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, बाजार आदि की योजना बनाई जाती है। लेकिन पुस्तकालय के लिए कोई जगह नहीं बनाई जाती। आधुनिक शहरों के वास्तुकार मॉल, फास्ट रेल, यातायात के साधन, वातानुकूलित शारिंग सेंटर के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन ज्ञान-पुस्तकादि के चाहने वालों को दरकिनार कर दिया जाता है। महानारायण में तो पुस्तकालयों की स्थिति ठीक नहीं है।

—अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

Digitized by srujanika@gmail.com

एनटीए ने नीट-यूजी 2025 के प्रवेश पत्र जारी किए

किसानों की भुगतान में देरी का सम्पन्न करना पड़ रहा है। जिलेभर में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार को सरसों बेची है, लेकिन भुगतान प्रक्रिया भंडारण रसीदों की अनुपलब्धता के कारण अटकी हुई है। इससे किसान परेशान हैं और समितियों तथा खरीद केंद्रों के लगातार चक्कर काटने को मजबूत है। खरीद के बाद उपज वेयरहाउस में जमा करवाई जाती है, जहां से भंडारण रसीदें जारी की जाती हैं। यह रसीदें भुगतान प्रक्रिया की पहली आवश्यकता होती है, लेकिन श्रीगंगानगर जिले में वेयरहाउस प्रबंधन द्वारा अभी तक रसीदें संबंधित संस्थाओं को जारी नहीं की गई हैं। नतीजतन, भुगतान की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया कि उन्होंने सरसों सरकार को बेची, लेकिन भुगतान के लिए अभी तक कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई है।

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार शाम को नीट यूजी-2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। नीट यूजी 2025 की ऑफिसियल वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक पर कैडिडेट्स अपने नीट यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड डालकर अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। परीक्षा 4 मई की होगी। परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश 11.00 बजे से शुरू हो जाएगा और 1.30 बजे तक चलेगा।

एलन करियर इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलर पारिजात मिश्रा ने बताया कि एनटीए द्वारा जारी की गई एडमिट कार्ड गार्डलाइन के अनुसार पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड कम सेलफ डिकोरेशन अंडरटेकिंग को अच्छे से कंप्लीट करें। इसमें परीक्षार्थी को फोटो (जैसा आवेदन पत्र में अपलोड किया गया) चिपकाना है।

परीक्षार्थी अपना एक पोस्टकार्ड साइज फोटो एडमिट कार्ड के साथ संलग्न निर्धारित परफोर्म में चिपका कर परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त एक समानांतर पासपोर्ट साईंज फोटो भी लेकर आएं जोकि अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के काम आएगा। परीक्षार्थी को स्वयं के साइन परीक्षक के सामने ही करने होंगे। बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन घर से लगाकर लाना होगा। आधार कार्ड की ओरिजिनल अपडेटेड कॉपी लाने के बारे में पेज नंबर 3 पर उल्लेखित किया गया है।

ओरिजिनल आईडी साथ जरूर लाएं: मिश्रा ने बताया कि परीक्षार्थी ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड अथवा 12वीं क्लास का प्रवेश पत्र जिसमें कैडिडेट की फोटो आ रही हो, इनमें से कोई सी भी एक आईडी साथ लानी है। फोटो कॉपी किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगी। विद्यार्थियों को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा। पर्सनल पारदर्शी वॉटर बोतल, और यदि कोई दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाने होंगे।

ड्रेस कोड: मिश्रा ने बताया कि परीक्षार्थी कोई भी लाईट कलर ड्रेस पहन सकता है। छात्र ट्राउजर्स या पेट जिसमें कि कोई मेटल बटन नहीं हो तथा हाफ शर्ट या टी-शर्ट पहन सकते हैं। छात्राएं सलवार कुर्ता, लोगिंग, पेट या ट्राउजर्स, टी-शर्ट व कुर्ती पहन सकती हैं।

किसी में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। पैरों में हाई हील की सैंडल जूते बर्जित हैं, नर्मल स्लीपर्स या सामान्य जूते पहन सकते हैं। आभूषण या मेटल की चीजें जैसे ताबिज, कड़ा पहनकर नहीं जाना है।

इन पर रहेगा प्रतिबंध: परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना बर्जित है। एडमिट कार्ड, पोस्टकार्ड साईंज फोटो हेतु निर्धारित परफोर्म तथा ओरिजिनल आईडी कार्ड के अलावा कोई कागज नहीं ले जाया जा सकता।

परीक्षा कक्ष की स्थिति: ओएमआर शीट पर मुख्यतया: अपना रोल नंबर, पेपर कोड, बैचेचन पेपर बुकलेट नंबर तथा व्यक्तिगत विवरण को सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक भरें। ओबल भरते समय पेन की इंक दूसरे ओबल को ओवरलेप नहीं करे और न ही फैल करके ओएमआर को गंदा करो। कटिंग व ओवरराइटिंग, इरेजिंग भी नहीं करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी की गई।

आखातीज पर बाल विवाह न हो, बूँदी जिला प्रशासन ने रखी पैनी नजर

प्रभाव डालता है। सहायक निदशक, बाल अधिकारिता हुकम चंद जाजोरिया ने बताया कि अभियान की तैयारियां पूर्व से ही विभाग द्वारा सुनियोजित रूप से की जा रही हैं। गाँव-गाँव जाकर नुक्कड नाटकों, पोस्टर, आँड़ियो संदर्शनों और संवाद के जरिये जन-जगरूकता फैला कर आम नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्कालचाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसे निभाकर हम बच्चों को सुरक्षित और है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों, संबंधित विभागों के हितधारकों, व बाल संरक्षण समिति सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारिता व एकशन एड-यूनिसेफ द्वारा किया गया था जिससे बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम में सशक्त भूमिका निभा सकें। जिसमें एचसीएम रोपा जयपुर से संदर्भ व्यक्ति आये थे।

समन्वयक ज़हीर आलम ने बताया कि साथीनोंद्वारा ठाम स्तर पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साथीनों पंचायत स्तर पर समुदाय से संवाद कर रही है, किशोरियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रही है, और बाल विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही, वे ऐसे परिवारों की पहचान कर समय पर सूचना विभाग को उपलब्ध करा रही हैं। बाल विवाह की उपलब्धि करा रही है।

पाई जाती है। संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह मुक्त बूंदी अभियान जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस, एसएन एड-यूनिसेफ आदि का साझा अभियान है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिसे मैं किसी भी बालिका या बालक का विवाह 18/21 वर्ष की वैधानिक आयु से पूर्व न हो। इस

पंचायत स्तर और स्कूलों में भी निरंतर जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर, आटड रीच वर्कर दीपिका वाशिष्ठ, चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक राम नारायण गुर्जर, पर्यवेक्षक पिंकी राठाड़, प्रीति बंशीवाल, सुमन बैरवा, जैंडर विशेषज्ञ विनीता अठावाल, सलोनी कुमावत, पन्नाधाय सुक्षा एवं सम्मान कैंड्र प्रबंधक पूर्णिमा गौतम, काउंसलर सलोनी शर्मा, अक्षिता मिश्रण, प्रिया

समान अवसरा वाला जावन द सकत इस अवसर पर एक्शन एड डिजला ह, जहा बाल विवाह का सभावना आध्यात्मिक माध्यम से ठामाण क्षत्रा, मिश्रण आद उपास्थ रहा।